Sl. No.	Name of proposal	Forest area involved	Status
16.	Diversion of forest land for revival of Ashok Paper Mills in Goalpara district, Assam.	11340 ha.	Pending with State Govt. for want of essential details.
17.	Diversion of forest land for setting up of Alumina Industry in favour of M/s. Utkal Alumina International Ltd., Orissa.	102 ha.	Pending with State Govt. for want of essential details
18.	Release of 1.10 ha. of forest land for construction of LPG tank road & pipeline at Baithkal in favour of Indo LPG Bottling Plant Ltd., Karnataka.	1.10 ha.	Pending with State Govt.
19.	Release of 6.02 ha. of forest land at Jambunatha village, Hospet M/s. Allum Karibasappa, Karnataka.	6.02 ha.	Pending with State Govt.
20.	Permission to lay underground pipeline and construction of Pump House in favour of M/s. Kalyani Steels Industries Ltd., Karnataka.	6.09 ha.	Pending with State Govt.
21.	Construction of Warehouse by Integrated Proteins Ltd., Gujarat.	01.0156 ha.	Rejected on 31.5.95

Doubling of Ernakulam-Quilon Railway Line

*436. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the proposal for the doubling of Ernakulam-Quilon Railway line *via* Kottayam and *via* Alleppy, and its present position?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): Two lines already exist between Ernakulam and Kayankulam, one *via* Kottayam and the other *via* Alleppey which serve the purpose of doubling. Between Kayankulam and Quilon dobuling has recently been completed. However, surveys for doubling of Kayankulam-Ernakulam *via* Alleppey/Kottayam has just been sanctioned.

Assistance to Maharashtra for Non-Formal Education

*437. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have provided assistance to State Government of Maharashtra to popularise non-formal education in the State;

(b) if so, the details thereof for the last three years, year-wise;

(c) whether Government have assessed the progress made by non-formal education in Maharashtra, particularly in Nagpur and the whole Vidarbha region; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) to (d) The Centrally sponsored scheme of Non-Formal Education (NFE) seeks to provide opportunities

for part-time education to out of school children in the age group of 6-14 years, who are not in a position to attend formal schools due to various socio-economic and cultural constraints. The scheme is essentially meant for ten educationally backward States. However, it also covers urban slums, hilly, desert and tribal areas and areas of concentration of working children in all other States/UTs.

Government of Maharashtra has not availed of financial assistance under the scheme. However, a number of Voluntary Agencies (VAs) are implementing the NFE scheme in Maharashtra. Details of grants released to them during the last three years are given below:

YEAR	NO. OF VAS	NO. OF CENTRES SANCTIONED	GRANT RELEASED (Rs. in lakhs)
1993-94	57	2225	101.91
1994-95	44	1825	98.01
1995-96	49	1900	128.58

The NFE Programmes being implemented by 34 voluntary agencies in the State have been evaluated by joint Evaluation Team consisting of the Field Adviser, NCERT, a representative of the State Government and a representative of a renowned voluntary agency. These include NFE programmes of 4 voluntary agencies in the Vidarbha region.

गन्ने की किस्म में सुधार लाने हेतु योजना

438. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने की किस्म में सुधार लाने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाने के संबंध में कोई योजनाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में गन्ने की किस्म राष्ट्रीय दृष्टि से भी घटिया होने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गन्ने के संबंध में किये जा रहे कृषि अनुसंधान की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां। तथापि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के लिए ये स्कीमें सीमित स्वरूप की हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ गन्ने से चीनी की प्राप्ति की मात्रा में सुधार लाने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना भी देश के 20 केन्द्रों में चल रहा है, जिसका मुख्यालय भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है। चीनी की अधिक उपज देने वाली किस्में, जैसे-को०- 86032, को०-87025, को०-87044, को०-87263 तथा को०एल०के० 7901 पहचानी गई हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा 1995-96 से उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 20 राज्यों में प्रचालन हेतु "गन्ना आधारित फसल पद्धति के सतत विकास" की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम में बीज उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाता है।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की क्वालिटी, प्राप्त होने वाली चीनी की प्रतिशतता के रूप में तुलनात्मक रूप से घटिया है। इसका कारण जैविक (रोग एवं नाशी जीव) और अजैविक (सूखा एवं जलप्लवता) दबाव तथा साथ ही चीनी मिलों में, विशेषकर बिहार में, पुरानी और अप्रचलित मशीनरी का होना है।

(ग) गन्ने से संबंधित कृषि अनुसंधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(1) विभिन्न वर्गों के लिए अधिक उपज/अधिक चीनी वाली किस्मों का उत्पादन करना।

(2) उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाल गलन, मुरझान, अगोला बेधक तथा उष्णकटिबंधीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए मुरझान, कंडुवा एवं लाल गलन (विशेषकर आन्ध्र प्रदेश तथा केरल में) रोग प्रतिरोधी किस्म के लिए उत्पादन करना।

(3) समेकित नाशी जीव प्रबंध सहित उत्पादन विधियों के स्थान विशिष्ट पैकजों का विकास करना।

(4) परम्परागत तथा सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकों का उपयोग करके अच्छे बीज का उत्पादन करना।

(5) उत्पादकों के अधिक लाभ के लिए उत्पादकता में सुधार हेतु फसल प्रणाली पर अनुसंधान करना।

(6) पेड़ी (रैटून) प्रबन्ध में सुधार करना।